

Q



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 9, 2004/भाद्र 18, 1926

No. 157]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 9, 2004/BHADRA 18, 1926

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2004

सं. एल-7/25(5)/2003-सीईआरसी.— केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सभी पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तों) विनियम, 2004 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तों) (पहला संशोधन) विनियम, 2004 है।

(2) इन विनियमों के विनियम 4, 9 और 13 1-10-2004 से प्रवृत्त होंगे, विनियम 5 और 10 याचिका सं. 67/2003 (स्वप्रेरणा) में उस तारीख के आदेश के अनुसार 7 जुलाई, 2004 से प्रवृत्त होंगे और सभी अन्य विनियम 1.4.2004 से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. विनियम 20 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 20 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“ 20. ऋण-ईक्विटी अनुपात : (1) विद्यमान उत्पादन केन्द्रों की दशा में, 31.3.2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए टैरिफ के नियतन हेतु आयोग द्वारा विचार किए गए ऋण-ईक्विटी अनुपात पर टैरिफ के अवधारण के लिए विचार किया जाएगा।

(2) ऐसे उत्पादन केन्द्रों, जिनके लिए विनिधान अनुमोदन 1.4.2004 से पूर्व प्रदान किया गया था और जिनको 1.4.2004 से 31.3.2009 की अवधि के दौरान

वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किए जाने की संभावना है, की दशा में, 70: 30 के अनुपात में ऋण-ईक्विटी पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह कि जहां लगाई गई ईक्विटी 30% से कम है, वहां टैरिफ के अवधारण के प्रयोजन के लिए लगाई गई वास्तविक ईक्विटी पर विचार किया जाएगा ।

परंतु यह और कि जहां उत्पादन कंपनी आयोग के समाधानप्रद रूप में उस लगाई गई ईक्विटी को सिद्ध करने में समर्थ है जो साधारण जनता के हित में 30% से अधिक थी वहां आयोग समुचित मामलों में टैरिफ के अवधारण के प्रयोजन के लिए 30% से उच्चतर ईक्विटी पर विचार कर सकता है :

(3) ऐसे उत्पादन केन्द्रों की दशा में, जिनके लिए विनिधान अनुमोदन 1.4.2004 को या उसके पश्चात् प्रदान किया गया है, टैरिफ के अवधारण के प्रयोजन के लिए 70: 30 के अनुपात में ऋण-ईक्विटी पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां लगाई गई ईक्विटी 30% से कम है, वहां लगाई गई वास्तविक ईक्विटी पर टैरिफ के अवधारण के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा ।

(4) यथास्थिति, उपखंड (1), (2) या (3) के अधीन प्राप्त ऋण-ईक्विटी का उपयोग ऋण पर ब्याज, ईक्विटी पर रिटर्न, अवक्षयण के लिए अग्रिम और विदेशी मुद्रा दर अंतर की संगणना के लिए किया जाएगा । ”

3. विनियम 24 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 24 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ 24. अननुसूचित विनियम (यू. आई.) प्रभार : (1) वास्तविक उत्पादन या वास्तविक निकासी तथा अनुसूचित उत्पादन या अनुसूचित निकासी के बीच होने वाले अंतर की गणना अननुसूचित विनियम (यू.आई.) प्रभारों के माध्यम से की जाएगी । उत्पादन केन्द्र के लिए यू.आई. इसके वास्तविक उत्पादन के बराबर होगा या इसके अनुसूचित उत्पादन

से कम होगा । फायदाग्राही के लिए यू. आई. इसकी कुल वास्तविक निकासी के बराबर होगा या इसकी कुल अनुसूचित निकासी से कम होगा । यू. आई. प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लाक के लिए निकाला जाएगा । सभी यू. आई. संव्यवहारों के लिए प्रभार-समय-ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी पर आधारित होंगे और निम्नलिखित दरें 1.4.2004 से 30.9.2004 तक लागू होंगी :

समय ब्लाकों की औसत फ्रिक्वेंसी	यू.आई. दर (पैसे प्रति किलो वाट घंटा)
50.5 एच ज्येड और उससे ऊपर	0.0
50.5 एच ज्येड से नीचे और 50.48 एच ज्येड तक	8.0
49.04 एच ज्येड से नीचे और 49.02 एच ज्येड तक	592.0
49.02 एच ज्येड से नीचे	600.0
50.5 एच ज्येड और 49.02 एच ज्येड के बीच	0.02 एच ज्येड स्टेप में लिनियर

(प्रत्येक 0.02 एच. जेड स्टेप उपरोक्त रेंज के भीतर 8.00 पैसे/के डब्ल्यू एच के समतुल्य होगा ।)

निम्नलिखित दरें 1.10.2004 से लागू होंगी:

समय ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी (एच जेड)		यू आई दर
निम्नलिखित	निम्नलिखित से	(पैसा प्रति के डब्ल्यू एच)
से नीचे	कम नहीं	
—	50.50	0.0
50.50	50.48	6.0
50.48	40.46	12.0
—	—	—

—	—	—
49.84	49.82	204.0
49.82	49.80	210.0
49.80	49.78	219.0
49.78	49.76	228.0
—	—	—
—	—	—
49.04	49.02	561.0
49.02	—	570.0

(प्रत्येक 0.02 एच जेड स्टेप 50.5 - 49.8 एच जेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 6.00 पैसे/के डब्ल्यू एच और 49.8 - 49.0 एच जेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 9.0 पैसे/के डब्ल्यू एच के समतुल्य होगा ।)

### टिप्पण

उपरोक्त औसत फ्रिक्वेंसी रेंज और यू. आई. दरें आयोग द्वारा पृथक् अधिसूचना के माध्यम से परिवर्तन के अध्वधीन हैं ।

(2) (i) 15 मिनट के किसी समय ब्लाक में घोषित क्षमता के 105% तक किसी उत्पादन और संपूर्ण दिन की औसत घोषित क्षमता की 101% तक की औसतता का गेमिंग के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा और उत्पादक, अनुसूचित उत्पादन से ऊपर ऐसे अधिक उत्पादन के लिए यू.आई. प्रभारों का हकदार होगा ।

(ii) विहित सीमा से परे किसी भी उत्पादन के लिए, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र अन्वेषण करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यहां कोई गेमिंग नहीं है और यदि प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कोई भी गेमिंग पाई जाती है तो ऐसे अतिरिक्त उत्पादन के कारण उत्पादन केन्द्र को देय तत्स्थानी यू आई प्रभारों में शून्य तक की कमी की जाएगी और रकम को फायदाग्राहियों के यू आई खाते में उत्पादन केन्द्र में उनकी क्षमता अंश में समायोजित किया जाएगा ।”

4. विनियम 26 का संशोधन :- मूल विनियम के विनियम 26 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ 26. विलंब संदाय अधिभार : यदि फायदाग्राही (फायदाग्राहियों) द्वारा क्षमता प्रभारों और ऊर्जा प्रभारों के बिलों के संदाय में बिलिंग की तारीख से 60 दिन की अवधि के बाद विलंब किया जाता है तो उत्पादन कंपनी द्वारा प्रति मास 1.25% की दर से विलंब संदाय अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा ” ।

5. विनियम 30 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 30 (क्षमता प्रभारों की बिलिंग और संदाय) के नीचे टिप्पण 1 और टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात् :-

#### “ टिप्पण - 1

केन्द्रीय सेक्टर उत्पादन केन्द्रों की कुल क्षमता का आबंटन समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, जो अनाबंटित भाग भी होता है । अनाबंटित भाग के ऐसे आबंटन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर कुल अनाबंटित क्षमता के लिए किया जाता है, को सदस्य-सचिव, प्रादेशिक विद्युत बोर्ड/प्रादेशिक ऊर्जा समिति अग्रिम में कम से कम 24 घंटे पूर्व प्रभावी करने वाले आबंटन में ऐसे परिवर्तन को अधिकथित करेगा । किसी भी फायदाग्राही का कुल क्षमता अंश उसकी क्षमता अंश और अनाबंटित भाग में से आबंटन का योग होगा । केन्द्रीय सरकार द्वारा अनाबंटित ऊर्जा के किसी भी विनिर्दिष्ट आबंटन के अभाव में, अनाबंटित ऊर्जा को अनाबंटित अंश के रूप में उसी अनुपात में अनाबंटित अंशों में जोड़ दिया जाएगा ।

#### टिप्पण - 2

फायदाग्राही क्षेत्र के भीतर/बाहर अन्य राज्यों को उनके आबंटित शेयर का भाग देने का प्रस्ताव कर सकेंगे । ऐसे मामलों में, विद्युत अंतरण की तकनीकी साध्यता पर निर्भर

रहते हुए और ऐसे अंतरणों के लिए क्षेत्र के भीतर/बाहर किसी अन्य राज्य के साथ उत्पादन कंपनी द्वारा किए गए विनिर्दिष्ट करार पर, फायदाग्राहियों के शेयर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पुनः आबंटित किए जा सकेंगे। जब ऐसा पुनः आबंटन किया जाता है तब ऐसे फायदाग्राही, जो शेयर अभ्यर्पित करते हैं, अभ्यर्पित शेयर के लिए क्षमता प्रभारों का संदाय करने के दायी होंगे। यथा उपरोक्त अभ्यर्पित और पुनः आबंटित क्षमता के लिए क्षमता प्रभार उन राज्यों द्वारा संदत्त किए जाएंगे जिनको अभ्यर्पित क्षमता आबंटित की गई थी। यथा उपरोक्त क्षमता की पुनः आबंटन की अवधि के सिवाय, उत्पादन केन्द्र के फायदाग्राही आबंटित क्षमता शेयरों के अनुसार, पूर्ण नियत प्रभारों का संदाय निरंतर करेंगे। ऐसे किसी पुनः आबंटन को प्रभावी करने के लिए सदस्य-सचिव, प्रादेशिक विद्युत बोर्ड/प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा अग्रिम में ऐसे आबंटन को प्रभावी करने के लिए कम से कम 24 घंटे पूर्व अधिसूचित करेगा।”

6. विनियम 31 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 31 के खंड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(viii) ‘अंतिम तारीख’ से उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के एक वर्ष पश्चात् समाप्त होने वाली पहले वित्तीय वर्ष की तारीख अभिप्रेत है।”

7. विनियम 36 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 36 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“36. ऋण-ईक्विटी अनुपात : (1) विद्यमान उत्पादन केन्द्र की दशा में, 31.3.2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए टैरिफ के नियतन हेतु आयोग द्वारा विचार किए गए ऋण-ईक्विटी अनुपात पर टैरिफ के अवधारण के लिए विचार किया जाएगा।

(2) ऐसे उत्पादन केन्द्रों की दशा में, जिनके लिए विनिधान अनुमोदन 1.4.2004 के पूर्व प्राप्त किया गया था और जिनको 1.4.2004 से 31.3.2009 तक की अवधि के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किए जाने की संभावना है, 70:30 के अनुपात में ऋण-ईक्विटी पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह कि जहां लगाई गई ईक्विटी 30% से कम है, वहां वास्तविक रूप से लगाई गई ईक्विटी पर टैरिफ के अवधारण के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा।

परंतु यह और कि जहां उत्पादन कंपनी आयोग के समाधानप्रद रूप में यह साबित करने में समर्थ हो जाती है कि 30% से अधिक ईक्विटी को लगाना साधारण जनता के हित में था, वहां आयोग समुचित मामलों में टैरिफ के अवधारण के प्रयोजन के लिए 30% से उच्चतर ईक्विटी पर विचार किया जा सकेगा :

(3) ऐसे उत्पादन केन्द्रों की दशा में, जिनके लिए विनिर्माण अनुमोदन 1.4.2004 को या उसके पश्चात् प्रदान किया गया है, टैरिफ के अवधारण के प्रयोजन के लिए 70:30 के अनुपात में ऋण-ईक्विटी पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह कि जहां लगाई गई ईक्विटी 30% से कम है, वहां वास्तविक रूप में लगाई गई ईक्विटी पर टैरिफ के अवधारण के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा।

(4) यथास्थिति, उपखंड (1), (2) या (3) के अधीन प्राप्त ऋण-ईक्विटी का उपयोग ऋण पर ब्याज, इक्विटी पर रिटर्न, अवक्षयण के लिए अग्रिम और विदेशी मुद्रा दर अंतर की संगणना के लिए किया जाएगा।”

8. विनियम 42 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 42 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ 42. अननुसूचित विनियम (यू. आई.) प्रभार : (1) वास्तविक उत्पादन या वास्तविक निकासी तथा अनुसूचित उत्पादन या अनुसूचित निकासी के बीच होने वाले अंतर की गणना अननुसूचित विनियम (यू.आई.) प्रभारों के माध्यम से की जाएगी। उत्पादन केन्द्र के लिए यू.आई. इसके वास्तविक उत्पादन के बराबर होगा या इसके अनुसूचित उत्पादन से कम होगा। फायदाग्राही के लिए यू. आई. इसकी कुल वास्तविक निकासी के बराबर होगा या इसकी कुल अनुसूचित निकासी से कम होगा। यू. आई. प्रत्येक 15-मिनट के

समय ब्लाक के लिए निकाला जाएगा । सभी यू. आई. संव्यवहारों के लिए प्रभार समय-ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी पर आधारित होंगे और निम्नलिखित दरें 1.4.2004 से 30.9.2004 तक लागू होंगी :

समय ब्लाकों की औसत फ्रिक्वेंसी	यू.आई. दर (पैसे प्रति किलो वाट घंटा)
50.5 एच ज्येड और उससे ऊपर	0.0
50.5 एच ज्येड से नीचे और 50.48 एच ज्येड तक	8.0
49.04 एच ज्येड से नीचे और 49.02 एच ज्येड तक	592.0
49.02 एच ज्येड से नीचे	600.0
50.5 एच ज्येड और 49.02 एच ज्येड के बीच	0.02 एच ज्येड स्टेप में लिनियर

(प्रत्येक 0.02 एच. जेड स्टेप उपरोक्त रेंज के भीतर 8.00 पैसे/के डब्ल्यू एच के समतुल्य होगा ।)

निम्नलिखित दरें 1.10.2004 से लागू होंगी:

समय ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी (एच ज़ेड)	यू आई दर	
निम्नलिखित से नीचे	निम्नलिखित से कम नहीं	(पैसा प्रति के डब्ल्यू एच)
—	50.50	0.0
50.50	50.48	6.0
50.48	40.46	12.0
—	—	—
—	—	—
49.84	49.82	204.0
49.82	49.80	210.0
49.80	49.78	219.0



49.78	49.76	228.0
—	—	—
—	—	—
49.04	49.02	561.0
49.02	—	570.0

(प्रत्येक 0.02 एच जेड स्टेप 50.5 - 49.8 एच जेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 6.00 पैसे/के डब्ल्यू एच और 49.8 - 49.0 एच जेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 9.0 पैसे/के डब्ल्यू एच के समतुल्य होगा ।)

### टिप्पण

उपरोक्त औसत फ्रिक्वेंसी रेंज और यू. आई. दरें आयोग द्वारा पृथक् अधिसूचना के माध्यम से परिवर्तन के अध्वधीन हैं ।

(2) (i) 15 मिनट के किसी समय ब्लाक में घोषित क्षमता के 105% तक किसी उत्पादन और संपूर्ण दिन की औसत घोषित क्षमता की 101% तक की औसतता का गेमिंग के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा और उत्पादक, अनुसूचित उत्पादन से ऊपर ऐसे अधिक उत्पादन के लिए यू.आई. प्रभारों का हकदार होगा ।

(ii) विहित सीमा से परे किसी भी उत्पादन के लिए, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र अन्वेषण करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यहां कोई गेमिंग नहीं है और यदि प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कोई भी गेमिंग पाई जाती है तो ऐसे अतिरिक्त उत्पादन के कारण उत्पादन केन्द्र को देय तत्स्थानी यू आई प्रभारों में शून्य तक की कमी की जाएगी और रकम को फायदाग्राहियों के यू आई खाते में उत्पादन केन्द्र में उनकी क्षमता अंश में समायोजित किया जाएगा ।”

9. विनियम 44 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 44 के स्थान पर, निम्नलिखित

विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ 44. विलंब संदाय अधिभार : यदि फायदाग्राही (फायदाग्राहियों) द्वारा क्षमता प्रभारों और ऊर्जा प्रभारों के बिलों के संदाय में बिलिंग की तारीख से 60 दिन की अवधि के

बाद विलंब किया जाता है तो उत्पादन कंपनी द्वारा प्रति मास 1.25% की दर पर विलंब संदाय अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा ।”

10. विनियम 48 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 48 (क्षमता प्रभारों की बिलिंग और संदाय) के खंड (i) के नीचे टिप्पण 1 और टिप्पण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात्:-

#### “ टिप्पण - 1

केन्द्रीय सेक्टर उत्पादन केन्द्रों की कुल क्षमता का आबंटन समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, जो अनाबंटित भाग भी होता है । अनाबंटित भाग के ऐसे आबंटन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर कुल अनाबंटित क्षमता के लिए किया जाता है, को सदस्य-सचिव, प्रादेशिक विद्युत बोर्ड/प्रादेशिक ऊर्जा समिति अग्रिम में कम से कम 24 घंटे पूर्व प्रभावी करने वाले आबंटन में ऐसे परिवर्तन को अधिकथित करेगा । किसी भी फायदाग्राही का कुल क्षमता अंश उसकी क्षमता अंश और अनाबंटित भाग में से आबंटन का योग होगा । केन्द्रीय सरकार द्वारा अनाबंटित ऊर्जा के किसी भी विनिर्दिष्ट आबंटन के अभाव में, अनाबंटित ऊर्जा को अनाबंटित अंश के रूप में उसी अनुपात में अनाबंटित अंशों में जोड़ दिया जाएगा ।

#### टिप्पण - 2

फायदाग्राही क्षेत्र के भीतर/बाहर अन्य राज्यों को उनके आबंटित शेयर का भाग देने का प्रस्ताव कर सकेंगे । ऐसे मामलों में, विद्युत अंतरण की तकनीकी साध्यता पर निर्भर रहते हुए और ऐसे अंतरणों के लिए क्षेत्र के भीतर/बाहर किसी अन्य राज्य के साथ उत्पादन कंपनी द्वारा किए गए विनिर्दिष्ट करार पर, फायदाग्राहियों के शेयर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पुनः आबंटित किए जा सकेंगे । जब ऐसा पुनः आबंटन किया जाता है तब ऐसे फायदाग्राही, जो शेयर अभ्यर्पित करते हैं, अभ्यर्पित शेयर के लिए क्षमता प्रभारों का संदाय करने के दायी होंगे । यथा उपरोक्त अभ्यर्पित और पुनः आबंटित क्षमता के लिए क्षमता प्रभार उन राज्यों द्वारा संदत्त किए जाएंगे जिनको अभ्यर्पित क्षमता आबंटित की गई थी । यथा उपरोक्त क्षमता की पुनः आबंटन की अवधि के सिवाय, उत्पादन केन्द्र के फायदाग्राही आबंटित क्षमता शेयरों के अनुसार, पूर्ण नियत प्रभारों का संदाय निरंतर करेंगे । ऐसे किसी पुनः आबंटन को प्रभावी करने के लिए

सदस्य-सचिव, प्रादेशिक विद्युत बोर्ड/प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा अग्रिम में ऐसे आबंटन को प्रभावी करने के लिए कम से कम 24 घंटे पूर्व अधिसूचित करेगा । ”

11. विनियम 54 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 54 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ 54. ऋण-ईक्विटी अनुपात : (1) विद्यमान परियोजना की दशा में, 31.3.2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए टैरिफ के नियतन हेतु आयोग द्वारा विचार किए गए ऋण-ईक्विटी अनुपात पर विचार किया जाएगा ।

(2) ऐसी पारेषण प्रणाली की दशा में, जिसके लिए विनिधान अनुमोदन 1.4.2004 से पूर्व प्रदान किया गया था और जिसे 1.4.2004 से 31.3.2009 की अवधि के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किए जाने की संभावना है, 70:30 के अनुपात में ऋण-ईक्विटी पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह कि जहां लगाई गई ईक्विटी 30% से कम है वहां, टैरिफ के अवधारण के प्रयोजन के लिए लगाई गई वास्तविक ईक्विटी पर विचार किया जाएगा,

परंतु यह और कि जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग के समाधानप्रद रूप में यह साबित करने में समर्थ हो जाता है कि 30% से अधिक लगाई गई ईक्विटी साधारण जनता के हित में थी, वहां आयोग समुचित मामलों में टैरिफ के अवधारण के प्रयोजन के लिए 30% से उच्चतर ईक्विटी पर विचार कर सकेगा, :

(3) ऐसी पारेषण प्रणाली की दशा में, जिसके लिए विनिधान अनुमोदन 1.4.2004 को या उसके पश्चात् प्रदान किया गया था, टैरिफ के अवधारण के प्रयोजन के लिए 70:30 के अनुपात में ऋण-ईक्विटी पर विचार किया जाएगा :

परंतु यह कि जहां लगाई गई ईक्विटी 30% से कम है, वहां लगाई गई वास्तविक ईक्विटी पर टैरिफ के अवधारण के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा ।

(4) यथास्थिति, उपखंड (1), (2) या (3) के अधीन प्राप्त ऋण-ईक्विटी का उपयोग ऋण पर ब्याज, इक्विटी पर रिटर्न, अवक्षयण के लिए अग्रिम और विदेशी मुद्रा दर अंतर की संगणना के लिए किया जाएगा । ”

12. विनियम 60 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 60 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“ 60. प्रोत्साहन :- (1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित सूत्र के अनुसार, विनियम 51 के अधीन विहित लक्ष्य उपलब्धता से परे वार्षिक उपलब्धता में बढ़ाए गए प्रत्येक प्रतिशतता बिन्दु के लिए ईक्विटी के 1% की दर से प्रोत्साहन का हकदार होगा ।

प्रोत्साहन = ईक्विटी x [ वार्षिक प्राप्त उपलब्धता – लक्ष्य उपलब्धता ] / 100

(2) प्रोत्साहन को दीर्घकालिक ग्राहकों द्वारा वर्ष के लिए उनकी औसत आबंटित पारेषण क्षमता के अनुपात में बांटा जाएगा। ”

13. विनियम 62 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 62 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“ 62. विलंब संदाय अधिभार : यदि फायदाग्राही (फायदाग्राहियों) द्वारा पारेषण प्रभारों के बिलों के संदाय में बिलिंग की तारीख से 60 दिन की अवधि के बाद विलंब किया जाता है तब पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रति मास 1.25% की दर से विलंब संदाय अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा । ”

14. टैरिफ फाइल करने वाले प्ररूप का प्रतिस्थापन : मूल विनियम के परिशिष्ट 1, भाग 2 में टैरिफ फाइल करने वाले प्ररूप (हाइड्रो)-प्ररूप 17-शीर्षक “प्रचालन और रख रखाव व्ययों की संगणना” के स्थान पर इन विनियमों के साथ प्रकाशित प्ररूप को रखा जाएगा ।

*अमित सिंह*

ए. के. सचान, सचिव

[विज्ञापन-3/4/असा./150/04]

प्ररूप 17

प्रचालन और रखरखाव व्ययों की संगणना												
ऊर्जा केन्द्र का नाम : (रुपए लाख में)												
	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	औस- त 1998-99 से 2002-03	आधार 2003-04	टैरिफ अवधि				
								2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मामला-1 : 1998-99 से 2002-03 के लिए उपलब्ध ओ एंड एम आंकड़े												
(वास्तविक तारीख के आधार पर आधारिक ओ एंड एम)												
(क) कुल ओ एंड एम व्यय												
(ख) प्रसामान्य ओ एंड एम व्यय*												
-- अतिरिक्त सुरक्षा व्यय												
-- सेलिटेशन												
-- अतिरिक्त कर्मचारिवृद्ध												
-- कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)												
(ग) ओ एंड एम आधार की संगणना (क-ख)						ई	एक्स = ई x (1.04) <sup>3</sup>	XX (1.04)	XX (1.04) <sup>2</sup>	XX (1.04) <sup>3</sup>	XX (1.04) <sup>4</sup>	XX (1.04) <sup>5</sup>

2737 GI/04-4

मामला 2 : ऐसे केंद्र जिनके लिए 1998-99 से 2002-03 हेतु आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं													
स्थापित किए जाने का वर्ष													
ओ एंड एम आधार की संगणना**							वाई	XX (1.04)	XX (1.04) <sup>2</sup>	XX (1.04) <sup>3</sup>	XX (1.04) <sup>4</sup>	XX (1.04) <sup>5</sup>	
<p>* प्रसामान्य ओ एंड एम खर्च जैसे :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— घुसपैठ के कारण सुरक्षा खर्च (सामान्य सुरक्षा से भिन्न)</li> <li>— प्रसामान्य सेलिटेशन के कारण</li> <li>— संनिर्माण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कर्मचारिवृंद का पुनः नियोजन किया जा सकेगा। वर्षवार ब्यौरे दिए जाने हैं।</li> </ul> <p>** 2003-04 स्तर को लाने के लिए प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की दर पर बढ़ाया हुआ ओ एंड एम आधार = <math>(0.15 \times \text{पूंजी लागत})</math>  उदाहरणार्थ : यदि 2000-01 में लगाए गए संयंत्र की पूंजी लागत 1000 करोड़ रुपए है तो 2003-04 के लिए आधार निम्नलिखित रूप में संगणित किया जाएगा :-  2003-04 के लिए आधार ओ एंड एम = <math>(0.15 \times 1000) \times (1.04)^3</math> करोड़ रुपए</p>													
													(याचिकाकर्ता)

### स्पष्टीकारक ज्ञापन

विनियम 1 के खण्ड (2) में यथाविनिर्दिष्ट कुछ संशोधित विनियम 1.4.2004 से अर्थात् उस तारीख से प्रभावी हैं जिस तारीख से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तों) विनियम, 2004 (मूल विनियम) लागू हो गए हैं। मूल विनियमों के अधीन टैरिफ, प्रोत्साहन आदि को अवधारित नहीं किया गया है। अतः टैरिफ, प्रोत्साहन अवधारण, आदि वाले संशोधन 1.4.2004 से लागू हैं।

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd September, 2004

**No. L-7/25(5)/2003-CERC.**— In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2004, hereinafter referred to as "the principal regulations", namely :—

1. **Short title and commencement:** (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2004.  
  
(2) Regulations 4, 9 and 13 of these regulations shall come into force from 1.10.2004, regulations 5 and 10 have come into force from 7<sup>th</sup> July 2004 in terms of order of that date in Petition No 67/2003 (suo motu) and all other regulations shall be deemed to have come into force with effect from 1.4.2004.
2. **Amendment of Regulation 20:** For Regulation 20 of the principal regulations, following shall be substituted, namely:-  
  
"20. **Debt-Equity Ratio.** (1) In case of the existing generating stations, debt-equity ratio considered by the Commission for fixation of tariff for the period ending 31.3.2004 shall be considered for determination of tariff.

(2) In case of the generating stations for which investment approval was accorded prior to 1.4.2004 and which are likely to be declared under commercial operation during the period from 1.4.2004 to 31.3.2009, debt-equity in the ratio of 70:30 shall be considered:

Provided that where deployment of equity is less than 30%, the actual equity deployed shall be considered for the purpose of determination of tariff.

Provided further that the Commission may in appropriate cases consider equity higher than 30% for the purpose of determination of tariff, where the generating company is able to establish to the satisfaction of the Commission that deployment of equity more than 30% was in the interest of general public;

(3) In case of the generating stations for which investment approval is accorded on or after 1.4.2004, debt-equity in the ratio of 70:30 shall be considered for the purpose of determination of tariff:

Provided that where deployment of equity is less than 30%, the actual equity deployed shall be considered for the purpose of determination of tariff.

(4) The debt and equity amount arrived at in accordance with above sub-clause (1), (2) or (3), as the case may be, shall be used for calculation of interest on loan, return on equity, advance against depreciation and foreign exchange rate variation."

3. **Amendment of Regulation 24:** For Regulation 24 of the principal regulations, following shall be substituted, namely:-



**"24. Unscheduled Interchange(UI) Charges:** (1) Variation between actual generation or actual drawal and scheduled generation or scheduled drawal shall be accounted for through Unscheduled Interchange (UI) Charges. UI for a generating station shall be equal to its actual generation minus its scheduled generation. UI for a beneficiary shall be equal to its total actual drawal minus its total scheduled drawal. UI shall be worked out for each 15-minute time block. Charges for all UI transactions shall be based on average frequency of the time block and the following rates shall apply from 1.4.2004 to 30.9.2004:

Average Frequency of time block	UI Rate (Paise per kWh)
50.5 Hz and above	0.0
Below 50.5 Hz and up to 50.48 Hz	8.0
Below 49.04 Hz and up to 49.02 Hz	592.0
Below 49.02 Hz	600.00
Between 50.5 Hz and 49.02 Hz	linear in 0.02 Hz step

(Each 0.02 Hz step is equivalent to 8.0 paise /kWh within the above range)

The following rates shall apply with effect from 1.10.2004:

Average frequency of time block (Hz)		UI Rate
Below	Not below	(Paise per kWh)
---	50.50	0.0
50.50	50.48	6.0
50.48	50.46	12.0
---	---	---
---	---	---
49.84	49.82	204.0
49.82	49.80	210.0
49.80	49.78	219.0
49.78	49.76	228.0
---	---	---
---	---	---
49.04	49.02	561.0
49.02	---	570.0

(Each 0.02 Hz step is equivalent to 6.0 paise/kWh in the 50.5-49.8 Hz frequency range, and to 9.0 paise/kWh in the 49.8-49.0 Hz frequency range.)

2737 GI/04-5

**Note**

The above average frequency range and UI rates are subject to change through a separate notification by the Commission.

(2) (i) Any generation up to 105% of the declared capacity in any time block of 15 minutes and averaging up to 101% of the average declared capacity over a day shall not be construed as gaming, and the generator shall be entitled to UI charges for such excess generation above the scheduled generation (SG).

(ii) For any generation beyond the prescribed limits, the Regional Load Despatch Centre shall investigate so as to ensure that there is no gaming, and if gaming is found by the Regional Load Despatch Centre, the corresponding UI charges due to the generating station on account of such extra generation shall be reduced to zero and the amount shall be adjusted in UI account of beneficiaries in the ratio of their capacity share in the generating station."

4. **Amendment of Regulation 26:** For Regulation 26 of the principal regulations, following shall be substituted, namely:-

"26. **Late Payment Surcharge:** In case the payment of bills of capacity charges and energy charges by the beneficiary or beneficiaries is delayed beyond a period of 60 days from the date of billing, late payment surcharge at the rate of 1.25% per month shall be levied by the generating company."

5. **Amendment of Regulation 30:** For Note 1 and Note 2 below clause (i) of regulation 30 of the principal regulations (Billing and Payment of Capacity Charges), following shall be substituted, namely:-

**"Note 1**

Allocation of total capacity of central sector generating stations is made by Central Government from time to time, which also has an unallocated portion. Allocation of the unallocated portion as made by the Central Government from time to time, for the total unallocated capacity shall be notified by the Member Secretary, Regional Electricity Board/Regional Power Committee in advance, at least 24 hours prior to such change in allocation taking effect. The total capacity share of any beneficiaries would be sum of its capacity share plus allocation out of the unallocated portion. In the absence of any specific allocation of unallocated power by the Central Government, the unallocated power shall be added to the allocated shares in the same proportion as the allocated shares.

**Note 2**

The beneficiaries may propose surrendering part of their allocated share to other States within/outside the region. In such cases, depending upon the technical feasibility of power transfer and specific agreements reached by the generating company with other States within/outside the region for such transfers, the shares of the beneficiaries may be re-allocated by the Central Government for a specific period. When such re-allocations are made, the beneficiaries who surrender the share shall not be liable to pay capacity charges for the surrendered share. The capacity charges for the capacity surrendered and reallocated as above shall be paid by the State(s) to whom the surrendered capacity is allocated. Except for the period of reallocation of capacity as above, the beneficiaries of the generating station shall continue to pay the full fixed charges as per allocated capacity shares. Any such reallocation shall be notified by the Member Secretary, Regional Electricity Board/Regional Power Committee in advance, at least 24 hours prior to such reallocation taking effect."

6. **Amendment of Regulation 31:** For Clause (viii) of regulation 31 of the principal regulations, following shall be substituted, namely:-

“(viii) ‘**Cut off date**’ means the date of first financial year closing after one year of the date of commercial operation of the generating station.”

7. **Amendment of Regulation 36:** For Regulation 36 of the principal regulations, following shall be substituted, namely:-

“36. **Debt-Equity Ratio.** (1) In case of the existing generating stations, debt-equity ratio considered by the Commission for fixation of tariff for the period ending 31.3.2004 shall be considered for determination of tariff.

(2) In case of the generating stations for which investment approval was accorded prior to 1.4.2004 and which are likely to be declared under commercial operation during the period 1.4.2004 to 31.3.2009, debt-equity in the ratio of 70:30 shall be considered:

Provided that where deployment of equity is less than 30%, the actual equity deployed shall be considered for the purpose of determination of tariff.

Provided further that the Commission may in appropriate cases consider equity higher than 30% for the purpose of determination of tariff, where the generating company is able to establish to the satisfaction of the Commission that deployment of equity more than 30% was in the interest of general public;

(3) In case of the generating stations for which investment approval is accorded on or after 1.4.2004, debt-equity in the ratio of 70:30 shall be considered for the purpose of determination of tariff:

Provided that where deployment of equity is less than 30%, the actual equity deployed shall be considered for the purpose of determination of tariff.

(4) The debt and equity amount arrived at in accordance with above sub-clause (1), (2) or (3), as the case may be, shall be used for calculation of interest on loan, return on equity, advance against depreciation and foreign exchange rate variation."

8. **Amendment of Regulation 42:** For Regulation 42 of the principal regulations, following shall be substituted, namely:-

"42. **Unscheduled Interchange (UI):** (1) Variation between actual generation or actual drawal and scheduled generation or scheduled drawal shall be accounted for through Unscheduled Interchange (UI) charges. UI for a generating station shall be equal to its actual generation minus its scheduled generation. UI for a beneficiary shall be equal to its total actual drawal minus its total scheduled drawal. UI shall be worked out for each 15-minute time block. Charges for all UI transactions shall be based on average frequency of the time block and the following rates shall apply from 1.4.2004 to 30.9.2004:

Average Frequency of time block	UI Rate (Paise per kWh)
50.5 Hz and above	0.0
Below 50.5 Hz and up to 50.48 Hz	8.0
Below 49.04 Hz and up to 49.02 Hz	592.0
Below 49.02 Hz	600.00
Between 50.5 Hz and 49.02 Hz	linear in 0.02 Hz step

(Each 0.02 Hz step is equivalent to 8.0 paise /kWh within the above range)

The following rates shall apply with effect from 1.10.2004:

Average frequency of time block (Hz)		UI Rate
Below	Not below	(Paise per kWh)
---	50.50	0.0
50.50	50.48	6.0
50.48	50.46	12.0
---	---	---
---	---	---
49.84	49.82	204.0
49.82	49.80	210.0
49.80	49.78	219.0
49.78	49.76	228.0
---	---	---
---	---	---
49.04	49.02	561.0
49.02	---	570.0

2737 GI/64-6

(Each 0.02 Hz step is equivalent to 6.0 paise/kWh in the 50.5-49.8 Hz frequency range, and to 9.0 paise/kWh in the 49.8-49.0 Hz frequency range.)

**Note**

The above average frequency range and UI rates are subject to change through a separate notification by the Commission.

(2) (i) Any generation up to 105% of the declared capacity in any time block of 15 minutes and averaging up to 101% of the average declared capacity over a day shall not be construed as gaming, and the generator shall be entitled to UI charges for such excess generation above the scheduled generation (SG).

(ii) For any generation beyond the prescribed limits, the Regional Load Despatch Centre shall investigate so as to ensure that there is no gaming, and if gaming is found by the Regional Load Despatch Centre, the corresponding UI charges due to the generating station on account of such extra generation shall be reduced to zero and the amount shall be adjusted in UI account of beneficiaries in the ratio of their capacity share in the generating station."

9. **Amendment of Regulation 44:** For Regulation 44 of the principal regulations, following shall be substituted, namely:-

"44. **Late Payment Surcharge:** In case the payment of bills of capacity charges and energy charges by the beneficiary or beneficiaries is delayed beyond a period of 60 days from the date of billing, late payment surcharge at the rate of 1.25% per month shall be levied by the generating company."

10. **Amendment of Regulation 48:** For note 1 and Note 2 below clause (i) of regulation 48 of the principal regulations (Billing and Payment of Capacity Charges), following shall be substituted, namely:-

**“Note 1**

Allocation of total capacity of central sector generating stations is made by Central Government from time to time, which also has an unallocated portion. Allocation of the unallocated portion as made by the Central Government from time to time, for the total unallocated capacity shall be notified by the Member Secretary, Regional Electricity Board/Regional Power Committee in advance, at least 24 hours prior to such change in allocation taking effect. The total capacity share of any beneficiaries would be sum of its capacity share plus allocation out of the unallocated portion. In the absence of any specific allocation of unallocated power by the Central Government, the unallocated power shall be added to the allocated shares in the same proportion as the allocated shares.

**Note 2**

The beneficiaries may propose surrendering part of their allocated share to other States within/outside the region. In such cases, depending upon the technical feasibility of power transfer and specific agreements reached by the generating company with other States within/outside the region for such transfers, the shares of the beneficiaries may be re-allocated by the Central Government for a specific period. When such re-allocations are made, the beneficiaries who surrender the share shall not be liable to pay capacity charges for the surrendered share. The capacity charges for the capacity surrendered and reallocated as above shall be paid by the State(s) to whom the surrendered capacity is allocated. Except for the period of reallocation of capacity as above, the beneficiaries of the generating station shall continue to pay the full fixed charges as per allocated capacity shares. Any such reallocation shall be notified by the Member Secretary, Regional Electricity Board/Regional Power Committee in advance, at least 24 hours prior to such reallocation taking effect.”

11. **Amendment of Regulation 54:** For Regulation 54 of the principal regulations, following shall be substituted, namely:-

"54. **Debt-Equity Ratio.** (1) In case of the existing project, debt-equity ratio considered by the Commission for fixation of tariff for the period ending 31.3.2004 shall be considered for determination of tariff.

(2) In case of the transmission system for which investment approval was accorded prior to 1.4.2004 and which is likely to be declared under commercial operation during the period 1.4.2004 to 31.3.2009, debt-equity in the ratio of 70:30 shall be considered:

Provided that where deployment of equity is less than 30%, the actual equity deployed shall be considered for the purpose of determination of tariff.

Provided further that the Commission may in appropriate case consider equity higher than 30% for the purpose of determination of tariff, where the transmission licensee is able to establish to the satisfaction of the Commission that deployment of equity more than 30% was in the interest of general public;

(3) In case of the transmission system for which investment approval is accorded on or after 1.4.2004, debt-equity in the ratio of 70:30 shall be considered for the purpose of determination of tariff:

Provided that where deployment of equity is less than 30%, the actual equity deployed shall be considered for the purpose of determination of tariff.

(4) The debt and equity amount arrived at in accordance with above sub-clause (1), (2) or (3), as the case may be, shall be used for calculation of interest on loan, return on equity, advance against depreciation and foreign exchange rate variation."



12. **Amendment of Regulation 60:** For Regulation 60 of the principal regulations, following shall be substituted, namely:-

"60. **Incentive** : (1) The transmission licensee shall be entitled to incentive @ 1% of equity for each percentage point of increase in annual availability beyond the target availability prescribed under regulation 51, in accordance with the following formula:

$$\text{Incentive} = \text{Equity} \times [\text{Annual availability achieved} - \text{Target availability}] / 100$$

(2) Incentive shall be shared by the long-term customers in the ratio of their average allotted transmission capacity for the year."

13. **Amendment of Regulation 62:** For Regulation 62 of the principal regulations, following shall be substituted, namely:-

"62. **Late Payment Surcharge**: In case the payment of bills of the transmission charges by the beneficiary or beneficiaries is delayed beyond a period of 60 days from the date of billing, late payment surcharge at the rate of 1.25% per month shall be levied by the transmission licensee."

14. **Substitution of Tariff Filing Form.** The tariff filing form (Hydro)-Form 17-titled "Calculation of Operation and Maintenance Expenses" of Appendix I Part II of the regulations shall be substituted by the form published along with these regulations.

A. K. SACHAN, Secy.  
[ADVT-3/4/Exty./150/04]

Note.— The principal regulations were notified in the Gazette of India (Extraordinary) Part III, Section 4 on 29-3-2004.

2737 GI/04-7



### **Explanatory Memorandum**

Some of the amended regulations as specified in Clause (2) of Regulation (1) are given effect from 1.4.2004, the date on which the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2004 (the principal regulations) became applicable. The tariff, incentive, etc under the principal regulations has not been determined. Therefore, the amendments having bearing on tariff, incentive determination, etc are given effect from 1.4.2004.